



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

No. 953]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. 89/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1448(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त में 95, शीर्ष “शर्ते”, के अंतर्गत, उपवाक्य (ii) के पश्चात् उप-उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(क) यदि किसी परियोजना के आयात के मामले में जिसके लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रमाणपत्र अनंतिम हो, आयातकर्ता आयात के समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे आयात पर देय सीमाशुल्क, यदि यह छूट न दी गई हो तो, के बराबर की राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम एक सौ छब्बीस महीने की अवधि तक के किसी अनुसूचित बैंक से प्राप्त सावधि जमा रशीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा करता हो और यदि आयातकर्ता आयात की तारीख से एक सौ बीस महीने की अवधि के भीतर मेगा पावर की अंतिम स्थिति से संबंधित प्रमाणपत्र को नहीं प्रस्तुत कर पाता है तो उक्त प्रतिभूति को ऐसे आयात पर देय सीमाशुल्क, यदि यह छूट न दी गई हो तो, के एवज में जब्त कर लिया जाएगा:

बशर्ते कि प्रोविजनल मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में फ़िक्स्ड डिपाजिट रशीद या बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई प्रतिभूति को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के उक्त संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए मेगा सार्टिफिकेट के अनुपात में ही निर्मुक्त किया जाएगा।”

[फा. सं. 354/94/2011-टीआरयू (भाग-1)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 87/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 17 नवम्बर, 2017, सा.का.नि. 1430(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2017

No. 89 /2017-Customs

G.S.R. 1448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the ANNEXURE, in Condition No.95, under the heading “Condition”, for sub-clause (a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) In case of imports for a project for which certificate regarding Mega Power Project status issued by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power is provisional, the importer furnishes a security in the form of a Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any Scheduled Bank for a term of one hundred and twenty-six months in the name of the President of India for an amount equal to the duty of customs payable on such imports but for this exemption, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation and if the importer fails to furnish the final mega power status certificate within a period of one hundred and twenty months from the date of importation, the said security shall be appropriated towards duty of customs payable on such imports but for this exemption:

Provided that in case of provisional Mega Power Projects, the security in the form of a Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee may be released proportionately as per the proportionate mega certificate issued by the said Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power.”.

[F. No. 354/94/2011-TRU(Pt-1)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 87/2017-Customs, dated the 17th November, 2017, published *vide* number G.S.R. 1430(E), dated the 17th November, 2017.